

उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग -1

संख्या: 268/35-1-2020 -स्वस-16/दी०/०५०/२०१९-स्व.प्र.अ.

लखनऊ :

दिनांक : 29 जून, 2020

भारत सरकार की अपेक्षानुसार प्रदेश सरकार द्वारा भी यूनाइटेड नेसन्स द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अंगीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत 17 गोल्स और 169 टारगेट हैं। इन गोल्स एवं टारगेट की प्राप्ति हेतु सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "एस0डी0जी0 नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट-2020" में 297 इंडीकेटर्स विकसित किए गए हैं, जिनमें से गोल संख्या 14 के 11 इंडीकेटर्स को छोड़कर शेष 286 इंडीकेटर्स उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। सतत विकास लक्ष्यों से संबन्धित साहित्य सामग्री एवं कार्मिकों की क्षमता वृद्धि से संबन्धित प्रशिक्षण मॉड्यूल इत्यादि नियोजन विभाग की वेबसाइट planning.up.nic.in, नीति आयोग की वेबसाइट niti.gov.in एवं मॉस्पी की वेबसाइट www.mospi.gov.in पर उपलब्ध है।

एस0डी0जी0 को भारत सरकार की अपेक्षानुसार जनपद/नगर निकाय/ ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जाता है तथा जनपद स्तर पर गोलवार नोडल विभाग/अधिकारी का निर्धारण, नोडल अधिकारियों के दायित्व एवं कार्य क्षेत्र, जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का गठन, टास्क फोर्स के दायित्व एवं कार्य क्षेत्र, एस0डी0जी0 सेल का गठन एवं दायित्व तथा कार्य क्षेत्र, मण्डल स्तरीय टास्क फोर्स व कार्य क्षेत्र तथा राज्य स्तरीय डैशबोर्ड सूचनाओं का अपडेशन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. गोलवार नोडल विभाग / अधिकारी

गोल सं०	सतत विकास लक्ष्य	नोडल / सह नोडल विभाग	नोडल अधिकारी
1	गरीबी उन्मूलन No Poverty	ग्राम्य विकास	जिला विकास अधिकारी
2	शून्य भुखमरी Zero Hunger	खाद्य एवं रसद / कृषि	जिला पूर्ति अधिकारी/ उप निदेशक, कृषि
3	उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली Good Health and Well Being	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा Quality Education	बेसिक / माध्यमिक शिक्षा	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला विद्यालय निरीक्षक
5	लैंगिक समानता Gender Equality	महिला कल्याण	जिला परिवीक्षा अधिकारी
6	स्वच्छ जल और स्वच्छता Clean Water and Sanitation	सिंचाई / ग्राम्य विकास/ पंचायतीराज	अधिशायी अभियंता सिंचाई / जिला विकास अधिकारी / जिला पंचायतराज अधिकारी

गोल सं०	सतत विकास लक्ष्य	नोडल / सह नोडल विभाग	नोडल अधिकारी
7	सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा Affordable and Clean Energy	ऊर्जा	अधिशाषी अभियंता विद्युत/ परियोजना अधिकारी, यूपी नेडा
8	उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि Decent Work and Economic Growth	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	उपायुक्त उद्योग
9	उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं Industry, Innovation and Infrastructure	औद्योगिक विकास	उपायुक्त उद्योग
10	असमानताओं में कमी Reduce Inequalities	समाज कल्याण	जिला समाज कल्याण अधिकारी
11	संवहनीय शहर और समुदाए Sustainable Cities and Communities	नगर विकास	नगर आयुक्त / अपर जिलाधिकारी
12	संवहनीय उपभोग और उत्पादन Responsible Consumption and Production	वन	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी
13	जलवायु परिवर्तन Climate Action	वन	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी
14	जलीय जीवों की सुरक्षा Life below Water		प्रदेश / जनपद में लागू नहीं
15	थलीय जीवों की सुरक्षा Life on land	वन	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी
16	शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं Peace, Justice and Strong Institutions	गृह	पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक
17	लक्ष्यों हेतु भागीदारी Partnership for Goals	वित्त	अपर जिलाधिकारी वित्त

2. नोडल विभाग /नोडल अधिकारियों के दायित्व एवं कार्य क्षेत्र

- गोल से संबन्धित विजन 2030 ,स्ट्रेटजी 2024 तथा वार्षिक एक्शन प्लान तैयार कराना।
- गोल से संबन्धित अन्य विभागों के साथ नियमित (मासिक) समीक्षा बैठक तथा प्रगति का अनुश्रवण।
- ऑनलाइन माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों से संबन्धित सूचनाओं का एकत्रीकरण को प्रोत्साहित करना।
- गोल से संबन्धित राज्य / जिला इंडिकेटर्स पर आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा राज्य / जिला स्तरीय डैश बोर्ड पर अपडेट कराना ।
- गोल से संबन्धित अन्य विभागों में नोडल अधिकारी/ कार्मिक नामित करना।
- संबन्धित अधिकारियों/कार्मिकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- संबन्धित सतत विकास लक्ष्य का ग्राम पंचायत स्तर/नगर निकाय स्तर तक प्रचार व प्रसार करना। उपरोक्त कार्यों के अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर टास्क फोर्स गठित की जाती है।

3. जनपद स्तरीय टास्क फोर्स

क्र०सं०	पदनाम	भूमिका
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	पुलिस आयुक्त (द्वारा नामित)/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी	सदस्य
5	नगर आयुक्त / अपर जिलाधिकारी	सदस्य
6	अपर जिलाधिकारी, वित्त	सदस्य
7	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
8	अधिशायी अभियंता, सिंचाई	सदस्य
9	अधिशायी अभियंता, विद्युत	सदस्य
10	उपायुक्त, उद्योग	सदस्य
11	उप निदेशक, कृषि	सदस्य
12	जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य
13	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
14	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
15	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
16	जिला परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य

17	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
18	परियोजना अधिकारी, यू०पी० नेडा	सदस्य
19	जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य
20	क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी	सदस्य
21	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन०आई०सी०)	विशेष आमंत्रि
22	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य-संयोजक

4.टास्क फोर्स के दायित्व एवं कार्य क्षेत्र

- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने हेतु नोडल विभाग/अधिकारियों से समन्वय कर जनपद का विजन डॉक्यूमेंट 2030,स्ट्रेटेजी 2024 तथा एक्शन प्लान तैयार कराना।
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तरीय योजनाओं की गोलवार/टारगेटवाइज/इंडीकेटरवाइज मैपिंग कराना तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था कराना ।
- जनपद स्तर पर तैयार किये गये इंडीकेटर्स को प्रत्येक माह अपडेट करना व इसकी प्रगति की सघन समीक्षा करना।
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से संबन्धित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं उनका नियमित अनुश्रवण करना।
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के परिप्रेक्ष्य में जिला विकास योजना(DDP)/ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (GPDP) तैयार कराना।
- नियोजन विभाग द्वारा विकसित स्टेट इंडिकेटर्स / डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर्स पर आंकड़ों का नोडल विभागों के माध्यम से एकीकरण कराना तथा इसका नियमित अनुश्रवण करना ।
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से संबन्धित नियोजन विभाग द्वारा तैयार कराये जा रहे राज्य स्तरीय डैश बोर्ड को नियमित अपडेट कराया जाना ।
- जिला स्तरीय डैश बोर्ड तैयार कराना तथा डैश बोर्ड पर विकास खंड/नगर निकायों के जिला स्तरीय इंडिकेटर्स के आंकड़ों को फीडिंग / अपडेट कराना।
- जिला स्तरीय इंडिकेटर के आधार पर जनपद के विकास खंडों व नगर निकायों की परस्पर रैंकिंग करना।
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर जिला स्तरीय /विकासखंड स्तरीय व ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- सतत विकास लक्ष्यों पर जनपद की प्रगति का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।

5. एसडीजी सेल का गठन

जनपद स्तर पर एसडीजी हेतु नोडल अधिकारी (मुख्य विकास अधिकारी) द्वारा जनपद के मुख्यालय स्तर पर एसडीजी सेल का गठन किया जाएगा। यह सेल जनपदीय टास्क फोर्स के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

एसडीजी सेल के दायित्व एवं कार्य क्षेत्र

- टास्क फोर्स के बैठकों का आयोजन।
- एसडीजी के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु नामित नोडल विभागों /नोडल अधिकारियों के मध्य समन्वय करना।
- नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के समय समय पर निर्गत निर्देशों का टास्क फोर्स के माध्यम से अनुपालन कराना।
- एसडीजी से संबन्धित जनपद में संचालित योजनाओं की प्रगति तथा राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय डैश बोर्ड पर आंकड़ों के फीडिंग का टास्क फोर्स के माध्यम से नियमित समीक्षा कराना।
- जिला स्तरीय इंडिकेटर्स के माध्यम से विकास खंडों / नगर निकायों की मासिक / वार्षिक रैंकिंग तैयार कर टास्क फोर्स को प्रस्तुत करना।

6. मण्डल स्तरीय टास्क फोर्स

मण्डल स्तरीय टास्क फोर्स का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

क्र०सं०	पदनाम	भूमिका
1	मंडलायुक्त	अध्यक्ष
2	मण्डल के जनपदों के जिलाधिकारीगण	सदस्य
3	मण्डल के जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4	अपर आयुक्त प्रशासन	सदस्य
5	संयुक्त विकास आयुक्त	सदस्य
6	उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या	सदस्य-संयोजक

मण्डल स्तरीय टास्क फोर्स का कार्य क्षेत्र

- मण्डल में एसडीजी से संबन्धित योजनाओं की प्रगति का सतत अनुश्रवण।
- जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के कार्यों की समीक्षा।
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर मण्डल स्तरीय अधिकारियों / कार्मिकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के समय समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराना।

7. राज्य स्तरीय डैशबोर्ड पर सूचनाओं का अपडेशन

- नियोजन विभाग द्वारा एन0आई0सी0 के सहयोग से तैयार किये जा रहे राज्यस्तरीय डैशबोर्ड पर स्टेट इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क (SIF)/ डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क (DIF) की सूचनाओं के

अपडेशन का कार्य संबंधित जनपद के अर्थ एवं संख्या अधिकारी द्वारा प्रत्येक गोल के लिये नामित नोडल अधिकारियों के सहयोग से सम्पादित कराया जायेगा।

- डैशबोर्ड हेतु इंडीकेटर्स पर सूचनाओं के अपडेशन कार्य का पर्यवेक्षण इंडीकेटर वैल्यू की पीरियोडिसिटी (Periodicity) के अनुसार जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा किया जाएगा।

(कुमार कमलेश)

अपर मुख्य सचिव।

पत्रांक: 268/35-1-2020-एम-16/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव-
ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद, कृषि, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार, सिंचाई, पंचायतीराज, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, औद्योगिक विकास, समाज कल्याण, नगर विकास, पर्यावरण, वन, गृह तथा वित्त विभाग, उपशासन।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त जिलाधिकारी।
- 7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
- 8- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 9- समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी / उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या।
- 10- समस्त सम्बन्धित राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी।
- 11- एस०आई०ओ०, एन०आई०सी०।
- 12- राज्य योजना आयोग के नोडल अधिकारी।

(अंकित कुमार अग्रवाल)

विशेष सचिव।